

भाग पांच : खण्ड दो

म. प्र. वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध का विनियम नियम 2007

अधिसूचना बमांक 2-39-04-सात-शा.-6 दिनांक 26 नवम्बर 2007 मध्य प्रदेश भू-राज: व संहिता, 1959 (बमांक 20 सन् 1959) की धारा 240 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (इकसठ) द्वारा रूढ़त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात्-

विनियम

1. संक्षिप्त नाम, वि: तार तथा प्रारम्भ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध या विनियमन विनियम, 2007 है।

2. कोई वृक्ष -

(क) किसी जलधारा, झरने या तालाब के किनारे के अन्तम कगार से 30 मीटर के भीतर,

(ख) किसी सड़क या बेलगाड़ी के रा: ते के मध्य से 15 मीटर के भीतर तथा किसी पगडंडी से 6 मीटर के भीतर,

(ग) किसी पिवड : थान से 30 मीटर की परिधि के भीतर किसी उपवन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में,

(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम अथवा उसके समान किसी अन्य योजना के अधीन वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के अधीन के क्षेत्र में,

(ङ) पड़ाव, कृ: तान, या ँ मशान : थल, गोठान, खेलहान बाजार या आबादी के लिए पृथक् रखे गये किसी क्षेत्र में, या

(च) पहाड़ी तथा 25 डिमी से अधिक ढलान वाले ऊँचे नीचे क्षेत्र पर, कोई वृक्ष न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, व उसका तना छीलकर घेरा बनाया जाएगा और नहीं उसे अन्यथा नुकसान पहुँचाया जाएगा।

: पं टीकरण - खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए जलधारा में ऐसी सिरताएँ, निदयाँ, छोटी निदयाँ और नाले सम्मिलित होंगे जिनमें साधारणतया दिसम्बर के अन्त तक पानी रहता है, किन्तु मानसून के दौरान पानी के बह निकलने से बनी छोटी अ: थायी नालियाँ सम्मिलित नहीं होंगी।

3. रूट एक माम पंचायत में एक माम पंचायत : तरीय समित होगी। ऐसी माम पंचायत के सामान्य प्रशासन समित के सम: त सद: य और : थातीय पटवारी ऐसी समित के सद: य होंगे। सामान्य प्रशासन समित का अध्यक्ष ऐसी समित का सभापित होगा और ऐसी समित का सचिव ऐसी समित का सद: य सचिव होगा। 4. विनियम 2 में विनिर्दिष्ट वृक्ष, माम पंचायत : तरीय समित की अनुशंसा पर तहसीलदार (जिसमें अपर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सम्मिलित है) की अनुज्ञा के बिना नहीं काटे जाएंगे :

परन्तु वृक्षों के काटे जाने या काटकर गिराये जाने के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी, यदि वृक्षों का काटा जाना या काटकर गिराया जाना, मध्य प्रदेश लोक वांनिकी अधिनियम, 2001 (बमांक 10 सन् 2001) के अनुसार है।

5. दखलरिहत या शासकीय भूमि पर खड़े वृक्ष कलेक्ट्र की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं काटे जाएंगे :

परन्तु माम पंचायत : तरीय समित सम्पत्क रूप से बुलाये गये सम्मिलन में पारित किए गये विधिमान्य संकल्प के आधार पर तहसीलदार (जिसमें अपर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सम्मिलित है) संहिता की धारा 234 के अधीन तैयार किये गये, नि: तार पडक के अनुसार केवल उस माम के निवासियों के वा: तिवक उपयोग के लिए माम में की दखल रिहत भूमि के बबूल प्रजाति के वृक्षों को या उनके भाग को काटने या हटाने की लिखित में अनुज्ञा दे सकेगा।

6. कोई भूमि: वामी, जिसकी भूमि वृक्षों से आवृद्धित है और जो : थायी खेती करने के लिए अनुपयुक्त है राज्य सरकार की उतनी खेती योग्य भूमि से, जो चालू बाजार दर से लगभग बराबर मूल्य की हो, विनियम करने के लिए कलेक्ट्र को आवेदन कर सकेगा :

परन्तु ऐसा विनियम दोनों पक्षों को अलाभकारी नहीं होगा तथा अन्य व्यक्तियों पर ऐसे विनियम का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो।

7. (1) जहाँ किसी राज: व अधिकारी को यह विव वास करने का कारण हो कि कोई वृक्ष इन विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में काटा गया है तो राज: व अधिकारी द्वारा या उसके आदेश के अधीन ऐसे वृक्ष की लकड़ी या कापर (कारपस) का अधिमहण किया जा सकेगा।

(2) जहाँ राज: व अधिकारी उपखण्ड अधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है वहाँ ऐसे अधिमहण की रिपोर्ट, उसके द्वारा पन्डित दिनों के भीतर, उपखण्ड अधिकारी को ऐसी कारवाई के लिए की जाएगी, जैसा कि वह म. प्र. भू राज: व संहिता, 1959 (ब. 20 वर्ष 59) की धारा 253 के अधीन करना उचित समझे।

8. (1) वृक्षों की कटाई से प्रोत्त वनोपज के परिवहन हेतु मध्य प्रदेश अभिवहन (वनोपज) विनियम 2000 लागू होंगे।

(2) अभिवहन में वनोपज का भार साधक कोई व्यक्ति किसी भी न अधिकारी, राज: व अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा, जब कभी उससे ऐसा करने को कहा जावे, उसके प्रभार में की वनोपज से सम्बन्धित पास या पासों को निरीक्षण हेतु प्र: तुत करेगा।

9. म. प्र. वृक्षों की कटाई का प्रतिषेध का विनियम 2002 एतद् द्वारा निरः त्रिक्रिये जाते हैं। परन्तु इस प्रकार निरसित विनियमों के उपबन्धों के अधीन की गई कोई कार्यवाही या पारित क्रिया गया आदेश, इन विनियमों के अधीन की गयी कोई कार्यवाही या पारित क्रिया आदेश समझा जावेगा।

